96

संख्या– /IV-3/2015–04(128)/2015

प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्ध कुम्भ मेला–2016,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2015

विषय– अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 के अर्न्तगत जनपद हरिद्वार में स्थायी सेतुओं की मरम्मत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1265/अ0कु0मे0/लो0नि0वि0/पान्टून पुल, दिनांक 20.11.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 के अर्न्तगत जनपद हरिद्वार में स्थायी सेतुओं की मरम्मत कार्य हेतु रू0 21.00 (रू0 इक्कीस लाख मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ हरिद्वार में 19 नग अस्थायी क्रेट सेतुओं का निर्माण एवं डिस्मेंटलिंग का कार्य हेतु शासनादेश संख्या–76/IV-3/2015–04(09)/2014, दिनांक 08.01.2015 के द्वारा लागत 959.82 लाख के सापेक्ष अवशेष बचत रु0 322.67 लाख के सापेक्ष रु0 21.00 लाख व्यय की स्वीकृति महामहिम राजयपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः–

(i) लोक निर्माण विभाग के पास उपलब्ध बचत की धनराशि में से विषयगत कार्य हेतु धनराशि रू0 21.00 (रू0 इक्कीस लाख मात्र) का धनराशि व्यय की जायेगी।

(ii) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(vi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(ix) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

(x) निर्माण कार्य का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा तथा कार्य की थर्ड पार्टी क्वालिटी चैकिंग कराई जाएगी।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगी।

(xii) अस्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। साथ ही यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।

(xiii) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण लोक निर्माण विभाग के स्तर से भी किया जाएगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–870/XXVII(2)/15, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–2165/IV-3/2015–04(128)/2015, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
11. वित्त अनुभाग–2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रईस अहमद)
अनु सचिव।